

कमल का बटन दबाएं



भाजपा को जिताएं



हमारे संकल्प



भाजपा ने हमेशा जन कल्याण को प्राथमिकता दी है, और इसके लिए हमने हमेशा केंद्र सरकार, अन्य राज्य सरकारों
और सभी संबंधित संस्थाओं के साथ सहयोग करके नागरिकों की समस्याओं का समाधान किया है।



• उदाहरण स्वरूप, **उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश** में भाजपा सरकारों ने **केन और बेतवा नदियों** को जोड़ने के लिए 40 साल की जल-विद्युत साझेदारी और समझौता किया है।



हमारी सरकार दिल्ली की स्वास्थ्य, यातायात, बिजली, पानी, परिवहन आदि से जुड़ी समस्याओं का बहाना, बहस या दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय, उसका पड़ोसी राज्यों, एमसीडी, एनडीएमसी एवं केंद्र सरकार के साथ सहयोग करके प्रभावी समाधान करेगी।

आप दिल्ली की असली आप-दा है

- आप-दा सरकार जल जीवन मिशन और आयुष्मान भारत जैसी केंद्र सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में असमर्थ रही, जिसके कारन दिल्ली के नागरिकों को अनेक सुविधाओं से वंचित रखा गया।
- आप-दा ने हमेशा जन कल्याण के मुकाबले राजनीतिक लाभ को प्राथमिकता दी है पंजाब में अपने ही सरकार के साथ पराली जलाने को रोकने में उनकी विफलता इसका स्पष्ट उदाहरण है।

- पिछले 10 वर्षों में, भाजपा की केंद्र सरकार ने डीबीटी के माध्यम से कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर भ्रष्टाचार और 'मिडिलमैन' को खत्म कर दिया है।
- राजस्थान में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाई है।





हम आप सरकार के व्यापक कुशासन और भ्रष्टाचार के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनाएंगे एवं डीटीसी, मोहल्ला क्लिनिक, क्लासरूम, एक्साइज पॉलिसी, जल बोर्ड, आदि से जुड़े घोटालों की जांच के लिए एसआईटी का गठन करेंगे।

आप-दा के घोटाले

- पूर्व मुख्यमंत्री ने कोविड महामारी के दौरान टैक्सपेयर के पैसों से शीशमहल का निर्माण कराया।
- दिल्ली उच्च न्यायालय ने **शराब घोटाले पर सीएजी (CAG) रिपोर्ट** को विधानसभा में पेश करने में देरी के लिए आप सरकार को फटकार लगाई, जिसमें ₹2,027 करोड़ के नुकसान का खुलासा हुआ था।
- दिल्ली जल बोर्ड में **₹28,000 करोड़ का घोटाला** हुआ।
- मोहल्ला क्लीनिक के जिरए 65,000 फर्जी लैब टेस्ट किए गए।

भाजपा की केंद्र सरकार ने पीएम श्री योजना के माध्यम से सभी राज्यों में 12,000 से अधिक स्कूलों को मॉडल संस्थानों में अपग्रेड किया है।



• मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा सहित अन्य राज्यों में भाजपा सरकारों ने युवाओं के लिए मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की योजनाएं लागू की हैं।



हम दिल्ली के जरूरतमंद छात्रों को **केजी से पीजी तक** सरकारी शैक्षिक संस्थानों में **मुफ्त शिक्षा प्रदान** करेंगे।

आप-दा का झूठ

- 2015 से 2022 के बीच आप सरकार ने 500 नए स्कूल खोलना का वादा किया था, लेकिन केवल 63 स्कूल ही खोले गए, वहीं 20 कॉलेजों के वादे में से आज तक एक भी सरकारी कॉलेज स्थापित नहीं किया गया।
- दिल्ली के **सरकारी स्कूलों में कक्षा 9** में **1 लाख से अधिक छात्र फेल हुए** (2023-24), वही 2021-22 में 28,531 फेल हुए।
- **कक्षाओं के निर्माण** में आप सरकार द्वारा **₹1,300 करोड़ के घोटालें** की पुष्टि की गई है। (दिल्ली विजिलेंस डायरेक्टरेट की रिपोर्ट के आधार पर)

- गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जरूरतमंद छात्रों को यूपीएससी और राज्य पीएससी की तैयारी के लिए विभिन्न माध्यमों से सहायता प्रदान कर रही हैं।
- **हरियाणा** में भाजपा सरकार ने हाल ही में राज्य एचपीएससी/यूपीएससी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को एकमुश्त वित्तीय सहायता और यात्रा लागत की प्रतिपूर्ति का वादा किया है।



हम दिल्ली के युवाओं को राज्य की विभिन्न **प्रतियोगी परीक्षाओं** की तैयारी में सक्षम बनाने के लिए:

- एकमुश्त ₹15,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे
- परीक्षा केंद्र तक की यात्रा लागत और आवेदन शुल्क की 2 अटेम्प्ट्स तक प्रतिपूर्ति करेंगे

आप-दा की लापरवाही

 आप-दा सरकार की घोर लापरवाही के कारण, 3 सिविल सर्विस अभ्यर्थियों की कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में डूबने से मौत हो गई।

• भाजपा की केंद्र सरकार ने यूपीए की तुलना में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए बजट आवंटन में 250% की वृद्धि की है।

- एससी/एसटी/ओबीसी उद्यमियों को पीएम मुद्रा योजना के तहत 40 करोड़ का ऋण प्रदान किया गया।
- केंद्र सरकार ने 2023 में 34.5 लाख से अधिक एससी छात्रों को **₹3,546 करोड़ की छात्रवृत्ति** वितरित की।
- गुजरात में भाजपा सरकार आईटीआई में नामांकित एससी छात्रों को ₹400 का प्रति माह स्टाइपेंड देती है।



हम दिल्ली में तकनीकी और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए **डॉ. बी. आर. अंबेडकर** स्टाइपेंड योजना शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत हम आईटीआई (ITI), स्किल सेंटर, पॉलिटेक्निक आदि में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को ₹1,000 का प्रति माह स्टाइपेंड प्रदान करेंगे।

आप-दा का झूठ

- आप-दा सरकार ने कभी भी एससी समुदाय के सर्वोत्तम हितों की परवाह नहीं की है पंजाब में एससी समुदाय से उपमुख्यमंत्री बनाने का उनका वादा आज भी अधूरा है।
- आप-दा सरकार ने 5 वर्षों में सिर्फ 5 एससी छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की।

2024 में, **महाराष्ट्र में एनडीए सरकार** ने ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए एक **कल्याण बोर्ड** की स्थापना की, जिसके तहत:



- ड्राइवरों को पेंशन, चिकित्सा उपचार और वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है
- उनके बच्चों को छात्रवृत्ति दी जा रही है





- ₹10 लाख तक का जीवन बीमा और ₹5 लाख तक का दुर्घटना बीमा प्रदान करेंगे
- उनके बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति देंगे
- **रियायती वाहन बीमा** प्रदान करेंगे

आप-दा का झूठ

- आप-दा सरकार ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए कल्याण बोर्ड स्थापित करने में विफल रही।
- आप-दा सरकार ने ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों के लिए 2015 से अब तक कोई कल्याणकारी योजना लागू नहीं की।

- भाजपा ने अंत्योदय के सिद्धांत पर चलते हुए, हमेशा समाज के सबसे कमजोर वर्गों को प्राथमिकता दी है।
- डोमेस्टिक वर्कर्स को मान्यता देने और उन्हें उनके अधिकार दिलाने वाली भाजपा एकमात्र सरकार है।
- मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए डोमेस्टिक वर्कर्स को मान्यता दी है।



हम सभी डोमेस्टिक वर्कर्स के लिए '**डोमेस्टिक वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड**' का गठन करेंगे जिसके अंतर्गत हम उन्हें:

- ₹10 लाख तक का जीवन बीमा और ₹5 लाख तक का दुर्घटना बीमा प्रदान करेंगे
- उनके बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्ति देंगे
- मातृत्व लाभ के रूप में 6 महीने की पेड मैटरनिटी लींव प्रदान करेंगे

आप-दा का झुठ

आप सरकार डोमेस्टिक वर्कर्स को मान्यता देने और उन्हें सामाजिक लाभ प्रदान करने में विफल रही है।

- पीएम स्विनिधि ने देश भर में 68 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को ₹50,000 तक के कोलैटरल-फ्री ऋण के माध्यम से आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है।
- दिल्ली में 1.9 लाख से अधिक स्ट्रीट वेंडर इस योजना के तहत लाभ उठा रहे हैं।





हम पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों की संख्या दोगुनी करेंगे।

आप-दा के राज में स्ट्रीट वेंडर्स पर हमला

- आप सरकार ने मनमाने तरीके से दिल्ली के स्ट्रीट वेंडर्स को बेदखल कर दिया, जिससे वह संकट में हैं।
- 2021 में स्ट्रीट वेंडर्स ने उत्पीड़न के खिलाफ मुख्यमंत्री आवास के बाहर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया था।